सत्यमेव जयते

श्री रामनरेश यादव

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

29 माघ, 1934 शक — भोपाल, सोमवार, 18 फरवरी 2013

माननीय सदस्यगण,

1. हम सबके लिए यह हार्दिक प्रसन्नता एवं गर्व का विषय है कि वर्ष 2012 राज्य के समग्र विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्ष रहा है। वर्ष 2011-12 में प्रदेश की विकास दर 12 प्रतिशत रही है। यही नहीं 11 वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर लक्ष्य से ज्यादा 10.2 प्रतिशत हासिल की गई। वर्ष 2011-12 में कृषि सेक्टर की वृद्धि दर अभूतपूर्व रूप से 18 प्रतिशत से अधिक रही है। खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। भारत सरकार ने प्रदेश को 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति जी से मुख्यमंत्री जी ने प्राप्त किया। उपलब्धियों के इस माहौल में विधान सभा के इस सत्र में मैं सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

2. मेरी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन तथा श्रेष्ठ वित्तीय मानकों को हासिल करने में मिली सफलता पर पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित हुआ है। राजकोषीय अनुशासन को बनाये रखते हुए हमने प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के संसाधन जुटाए हैं। वर्ष 2012 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित दरों पर 5870 रुपये वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रचलित दरों पर प्रति व्यक्ति आय 43,864 रुपये हो गई है। 2004-05 की तुलना में प्रचलित दरों पर यह पौने तीन गुने से भी अधिक है। विकास के लिये किये गए प्रतिबद्ध प्रयासों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आधार वर्ष 2004-05 की तुलना में स्थिर मूल्यों पर 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की विकास गतिविधियों के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के बावजूद मेरी सरकार राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के अंदर रखने में सफल हुई है। राज्य आयोजना व्यय के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में सफल रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजना व्यय की वृद्धि दर (ट्रेंड ग्रोथ) 19.45 प्रतिशत रही है। ऐसी प्रगति इसलिए संभव हुई क्योंकि जहाँ शासन ने आधारभूत ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी, वहीं कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में निवेश के लिए वातावरण निर्मित करने में सफलता हासिल की है।

तेजी से विकास के लिए सुशासन को आधारभूत समझ कर बहुत से प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया गया है।

3. मेरी सरकार का यह संकल्प रहा है कि विकास की गति न केवल तेज हो बल्कि विकास व्यापक और समावेशी हो। हमारे संविधान की भूमिका में ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को न्याय एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की गई है। मेरी सरकार ने लोक सरोकारों को तवज्जो देने की एक नई प्रशासनिक संस्कृति कायम की है। योजनाएं तो पहले भी बनाई जाती रही हैं, लेकिन मेरी सरकार ने प्रभावित वर्गों की राज्य स्तर पर हुई 29 पंचायतों में उनके द्वारा खुद अपनी बेहतरी के लिए दिये गए सुझावों को योजनाओं में परिणत किया है। आम आदमी की रचनात्मक प्रज्ञा का उपयोग करने के लिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की इस शैली को अपनाने में मध्यप्रदेश देश भर में अनूठा स्थान रखता है। पंचायतों का यह सिलसिला अभी भी जारी है। इनके आधार पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप, वृद्धजन पंचायत में आये सुझावों के आधार पर अनूठी 'मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना' शुरू की गयी है। युवा पंचायत में 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' ने आकार लिया और किसान महापंचायत में किसानों के लिए कार्यक्रमों, और सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए।

4. प्रदेश में पिछले कुछ सालों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और मजबूत करने में ऐतिहासिक सफलताएं मिली हैं। आज हमारी सड़कें प्रगति का साधन और सूचक दोनों हैं। पिछले साल लगभग 9 हजार कि.मी. सड़कों का विकास और विस्तार हुआ है। इन्हें मिलाकर पिछले 9 सालों में 90 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन हुआ है। पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशीप (पी.पी.पी.) योजना के अंतर्गत 25 राज्य राजमार्ग, जिनकी लंबाई लगभग 2400 कि.मी. है, को साढ़े चार हजार करोड़ की राशि से पूर्ण किया गया है तथा लगभग 150 कि.मी. सड़कें निर्माणाधीन हैं। मध्यप्रदेश, भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वी.जी.एफ.) योजना के अंतर्गत पूरे देश में सर्वाधिक राशि उपयोग करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 से कम आबादी वाले सामान्य और 250 से कम आबादी वाले आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में सड़कों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई है, अतः मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत पाँच सौ से कम आबादी वाले एक हजार से अधिक ग्रामों में अब तक 1943 कि. मी. सड़क बनाई गई है।

सड़कों से जुड़ने के फलस्वरूप गाँवों में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगी और कृषि उत्पादों को समय रहते बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और सुधार के लिये केन्द्र सरकार से निरन्तर आग्रह किया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और राष्ट्रव्यापी आवागमन बिना गतिरोध संपन्न हो सके।

5. प्रदेश के ग्रामीण मार्गों पर परिवहन के सस्ते एवं सुलभ साधन उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1991 में संशोधन कर ग्रामीण परिवहन सेवा का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए 1350 से अधिक मार्गों को चिन्हांकित कर सूत्रीकृत किया जा चुका है। प्रदेश में नागरिकों की सुविधा एवं अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से डीलर पाईंट इनरोलमेंट सिस्टम लागू किया गया है जिससे वाहन क्रय के समय डीलर के स्तर पर ही वाहन पंजीयन एवं रोड टेक्स आदि की औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी और वाहन स्वामी किसी भी समय पंजीयन करा सकेगा। 21 उपजेलों का उन्नयन कर उन्हें चरणबद्ध रूप से जिला जेल में परिणत करने का निर्णय लिया गया है।

6. मेरी सरकार ने प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिये तथा प्रदेश के आर्थिक विकास व नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, में ऊर्जा की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की रणनीति पर लगातार काम किया है। गाँवों में लगातार बिजली उपलब्ध कराने हेतु अटल ज्योति अभियान के रूप में असंभव से लगने वाले एक कार्य की सफल शुरुआत जबलपुर जिले से हुई है। फीडर विभक्तिकरण की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली और खेती-किसानी के लिये न्यूनतम 8 घंटे का विद्युत प्रदाय कर नये युग की शुरुआत की गई है। अटल ज्योति अभियान महज अनवरत बिजली प्रदाय का अभियान नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण इलाकों में लघु और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिये मददगार सिद्ध होगा। अगले कुछ माहों में प्रदेश के सभी जिलों में अटल ज्योति अभियान का लाभ पहुंचाने के लिये हम कृतसंकल्प हैं।

7. इस समय प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 10 हजार 231 मेगावाट है। इस क्षमता में मार्च 2014 तक 4 हजार 963 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य है। प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा उत्पादन में निवेश के लिये नई नीतियों को लागू किया गया है। देश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सोलर संयंत्र नीमच जिले में स्थापित हो रहा है।

लघु जल विद्युत्, बायोमास, सौर और पवन ऊर्जा की वर्तमान 448 मेगावाट की विद्युत् क्षमता को अगले वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने का लक्ष्य है।

8. खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में अनेक ठोस और दूरगामी परिणाम देने वाले ऐतिहासिक कदम उठाये गए हैं। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी कृषि ऋण, गेहूँ और धान के समर्थन मूल्य पर बोनस और 85 लाख मी. टन गेहूँ के उपार्जन जैसे कदमों के साथ सिंचाई के रकबे में वृद्धि का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन तीन गुना, धान का साढ़े-तीन गुना, चने का दो गुना एवं सोयाबीन का ढाई गुना हो गया है। इसी अवधि में बीज वितरण में आठ गुना से अधिक वृद्धि हुई है। उर्वरक वितरण तीन गुने से अधिक हो गया है। किसानों को उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सोसायटी स्तर पर अग्रिम भंडारण हेतु 59 करोड़ रुपए व्यय किये गये हैं। इसके फलस्वरूप मैदानी स्तर पर उर्वरक उपलब्धता की अनिश्चितता समाप्त की गई है और समय-समय पर खाद के दामों में की गई वृद्धि के बोझ से किसानों को बचाकर उन्हें लगभग 300 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया है।

अगली रबी के लिए गेहूँ के उपार्जन पर 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का बड़ा फैसला लिया गया है. इस वर्ष रुपये 1500 प्रति क्विन्टल की दर से गेहूँ खरीदी की जावेगी।

9. किसानों की सुविधा के लिये अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं। इनमें किसानों को वर्ष में दो बार विद्युत् बिल देने और प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष 1200 रुपये की फ्लेट रेट पर बिजली दिये जाने के निर्णय उल्लेखनीय हैं। खेती एवं उद्यानिकी की उन्नत तकनीकों से प्रदेश के किसानों का सीधा परिचय कराने के लिए मेरी सरकार किसानों के समूहों को विदेश भी भेजेगी।

मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न हल्कों में ओला वृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति अभी कुछ दिनों से बनी हुई है। मेरी सरकार संकट के इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और उनकी मदद के लिए हर संभव उपाय करेगी।

10. 1200 से भी अधिक बीज उत्पादन सहकारी समितियाँ गठित कर हम किसानों की सहभागिता से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। सरकार की बलराम तालाब और हलधर योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। 30 लाख किसान परिवारों को 8 हजार 700 करोड़ रुपये के ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अगले वर्ष सहकारी बैंकों से 12 हजार करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये जाएंगे। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गेहूँ, धान, मोटे अनाज की खरीदी के लिए ई-उपार्जन योजना लागू की गई है।

देश में पहली बार उपज का मूल्य सीधे कैश ट्रांसफर की व्यवस्था से उनके बैंक खातों में जमा किया गया। अकेले गेहूँ की बोनस सहित खरीदी की लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी गई। राज्य के किसान को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मेरी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

11. कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा किसान की आय व रोजगार को बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है। हमारे किसानों ने इन फसलों के उत्पादन में पिछले तीन वर्ष में ढाई गुना और सब्जी उत्पादन में तीन गुना वृद्धि की है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों में उद्यानिकी के प्रति रूझान तथा इस क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे अवसरों को दृष्टि में रखते हुए क्लस्टर एप्रोच को प्रोत्साहित किया गया है ताकि मूल्य संवर्धन और विपणन में किसानों को मदद मिल सके। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन तथा उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों तक नई तकनीकी ज्ञान पहुंचाने, आदान प्रदाय एवं व्यवसायीकरण से जुड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें संगठित करने का अभिनव प्रयोग कृषि तथा उद्यानिकी विभागों एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है।

12. कृषि उपज के भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिये मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग नीति 2012 लागू की गई है। विगत दो वर्ष में लगभग 6.48 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता विकसित की गई है। आगामी दो वर्षों में लगभग 60 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता विंकसित किये जाने की योजना है।

13. अपनी आय के लिये किसान सिर्फ अपनी फसल पर निर्भर न रह जाएं, इसलिए मेरी सरकार द्वारा किसान की आमदनी के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन गतिविधियों को विशेष महत्व दिया गया है। परिणामस्वरूप वर्ष 2004 की प्रति व्यक्ति प्रति दिन दुग्ध उपलब्धता 233 ग्राम आज बढ़कर 307 ग्राम हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में दुग्ध उत्पादन में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई है। देश का प्रथम गौ-अभ्यारण्य शाजापुर जिले के ग्राम सलारिया में प्रारंभ हुआ है। गौ-वंश के संरक्षण और उन्हें प्राकृतिक वातावरण देने की यह अनूठी पहल है। भारतीय देशी नस्लों की गायों के पशुपालकों के प्रोत्साहन की गोपाल पुरस्कार योजना का विस्तार विकासखण्ड स्तर तक किया गया है। पिछले वर्ष 40 नये पशु औषधालयों की स्थापना की गई है और 118 पशु औषधालयों का उन्नयन किया गया।

चल पशु चिकित्सा इकाइयों का विस्तार कर इस वर्ष 89 आदिवासी विकासखण्डों में संचालन किया जाएगा। प्रदेश में मत्स्य उद्योग की विकास दर अब तक की सर्वाधिक तेरह प्रतिशत रही है। मेरी सरकार द्वारा किसानों के समान मछुआरों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

14. सिंचाई के बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिए हमने जल प्रबंधन की रणनीति पर विशेष उत्साह के साथ काम किया है। जिसके चलते प्रदेश में पिछले नौ वर्षों में सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर करीब 25 लाख हेक्टेयर किया गया है। अंतिम छोर (टेल-एण्ड) तक नहरों का पानी पहुंचे इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। सिंचाई की निर्मित और उपयोग की जा रही क्षमता के अंतर को कम करने मेरी सरकार कमांड क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही रूपांकित क्षमता से अधिक सिंचाई कर हमने देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 63 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कमांड क्षेत्र के विकास कार्य किए गए थे।

इसकी तुलना में 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही 60 हजार हेक्टर क्षेत्र में विकास कार्य किये गये हैं। कमांड क्षेत्र के सभी खेतों तक समयानुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई जल के वितरण की रोटेशन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है जिससे सृजित सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सका है।

15. मेरी सरकार मालवा क्षेत्र के गिरते जलस्तर तथा वहाँ पीने के पानी की समस्या के निदान के लिए चिंतित रही है। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक पॉयलट परियोजना का निर्माण आरंभ किया गया है। जिसके अन्तर्गत नर्मदा नदी का 5 क्यूमेक जल उद्वहन कर क्षिप्रा नदी के उदगम पर छोड़ा जाएगा। इससे सिंहस्थ 2016 में पानी की उपलब्धता के अलावा लगभग 70 ग्रामों तथा 2 शहरों देवास एवं उज्जैन को पेयजल तथा पीथमपुर को औद्योगिक जल उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना को विस्तारित कर पार्वती, कालीसिंध एवं गंभीर नदियों में जल प्रवाहित कर 16 लाख एकड़ में सिंचाई तथा 70 शहरों एवं कस्बों एवं 3000 ग्रामों को पेयजल प्रदाय किया जाना परिकल्पित है।

16. पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण के लिये मेरी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। प्रदेश में पिछले साढ़े चार वर्ष में लगभग 48 हजार ग्रामीण बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की गई है। कम आबादी वाले ग्रामों में पानी पहुँचाने के संकल्प के तहत मुख्यमंत्री पेयजल योजना में लगभग दो हजार नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। फ्लोराइड आधिक्य वाली डेढ़ हजार बसाहटों में शुद्ध पेयजल का प्रबंध किया गया है। सतही जल स्त्रोतों के उपयोग के लिये नव-गठित मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 600 से अधिक ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है। जल निगम द्वारा ग्रामों की समूह जल विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान देगा।

17. कृषि विकास के साथ-साथ प्रदेश में गाँवों के विकास का समूचा परिदृश्य भी बदल रहा है। गाँवों के संतुलित विकास की एक सुचिंतित रणनीति के तहत सड़क, बिजली, पानी, आवास, नालियाँ और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा लागू पंच परमेश्वर योजना के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। इस योजना में नाली सहित आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिये जनसंख्या के मान से ग्राम पंचायतों को राशि दी गई है।

जिला पंचायतों को एकमुश्त एक-एक करोड़ रुपये और जनपद पंचायतों को 25 लाख रुपये दिये गये हैं। नल-जल योजनाओं और स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों के मामलों में ग्राम पंचायतों की सहायता करने के लिये विद्युत् कंपनियों को मेरी सरकार ने 75 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बीआरजीएफ कोष का फायदा अब प्रदेश के 30 जिलों को दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने की दृष्टि से ई-पंचायत कक्ष बनाये जा रहे हैं। प्रदेश की सभी पंचायतों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

18. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 84 हजार आवास बनाये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो रहा लक्ष्य तथा आवंटन प्रदेश के लिये अत्यल्प है। इस कमी को मेरी सरकार ने अपनी पहल से पूरी करने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन प्रारंभ किया है। जिसके जरिए प्रदेश के एक लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिये ऋण-सह-अनुदान योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

19. प्रदेश में 44 हजार से अधिक महिला स्वसहायता समूहों को आजीविका से जोड़ा गया है। इन समूहों द्वारा 18 करोड़ रुपये की बचत की गई है। प्रदेश के 10 जिलों में सघन ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत हो चुकी है। चरणबद्ध रूप में इसे राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

20. कुपोषण के अभिशाप को समाप्त करने के लिये मेरी सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। राज्य में 376 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 65-75 हजार गंभीर रूप से कुपोषित बालक-बालिकाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। आय.सी.डी.एस. अन्तर्गत प्रयासों से आगे बढ़कर कुपोषण को समाप्त करने के लिये अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से जिला केन्द्रित योजनाएं प्रारंभ की गई है।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में खुले शौच की कुरीति को मुक्त करने के लिये मर्यादा अभियान लागू किया गया है। प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 3 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर 12 हजार से अधिक गाँवों को इस कुरीति से मुक्त करने का लक्ष्य है।

मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से अपील करना चाहूंगा कि वे हमारी बहू-बेटियों-बहनों-माँओं की गरिमा की रक्षा के लिये इस अभियान को विशेष महत्व दें और इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े।

22. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत हमारा प्रदेश सार्वजनिक उपयोग की स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कार्यों में से 58 प्रतिशत स्थाई ग्रामीण परिसंपत्तियों हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। ग्रामीण अंचलों में अल्ट्रा स्माल बैंक खोलने का कार्य तेजी से हो रहा है। अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित 7 हजार से अधिक गाँव के पास अल्ट्रा बैंक सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इस सुविधा से मनरेगा की मजदूरी के अलावा अन्य शासकीय योजनाओं की सहायता राशि और छात्रवृत्तियाँ सीधे बैंक खातों में जमा हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर देश की 11 सम्मानित ग्राम पंचायतों में बैतूल जिले की साकादेही ग्राम पंचायत भी शामिल है।

23. जन सामान्य और विशेषकर किसानों के लिये राजस्व विभाग की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।

मेरी सरकार ने राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये भू-राजस्व संहिता में संशोधन किये हैं। इनमें तुच्छ आधारों पर सुनवाई की तिथि बढ़ाने की प्रवृति पर रोक लगाई गई है। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के 33 जिलों में खसरे के साथ नक्शे की नकल भी उपलब्ध कराई जा रही है। सभी तहसीलों के अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का कार्य 13 जिलों में चल रहा है। जल्द ही हम घर-घर खसरा-नक्शा-खतौनी की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं।

24. वनों का संरक्षण व संवर्धन तथा वनाश्रित स्थानीय जन-समुदाय की आजीविका का सुदृढ़ीकरण मेरी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। लघुवनोपजों का वनवासियों के आर्थिक उत्थान में महत्पूर्ण योगदान है। देश में पहली बार मेरी सरकार ने हर्रा, महुआ फूल, महुआ गुठली, नीमबीज, करंजबीज, लाख और अचार गुठली का समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसके अलावा चिरौंजी, शहद, माहुल पत्ता, आँवला और अन्य औषधीय वनोपजों के निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। राज्य में पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की दृष्टि से कई नये कदम उठाये गये हैं। पन्ना में बाघ पुनः स्थापना के प्रयासों को सफलता मिली है। देश में पहली बार विशालकाय गौर को कान्हा से बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लाया गया है।

25. राज्य के नगर आबादी में जबरदस्त वृद्धि के दबाव का सामना कर रहे हैं। अतः शहरों के समग्र विकास की दिशा में मेरी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। सभी 14 नगर निगमों तथा 96 नगरपालिकाओं की विकास योजनाएँ तैयार की गयी है। राज्य के अन्य 250 शहरों की विकास योजनाएँ इस वर्ष तैयार हो जाएंगी। बुनियादी विकास कार्यों के लिये 174 नगरीय निकायों को 1195 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है। पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिये 655 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया गया है। 140 नगर निकायों के लिये, जिनके पास स्वयं फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी, यह प्रबंध किया गया है। हाथठेला, साइकिल रिक्शा चालकों, हम्मालों और शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिये सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता की योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। केश शिल्पियों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ आरम्भ की जा रही हैं। नगरीय सुशासन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक, यांत्रिकी तथा स्वच्छता सेवा वर्गों की संरचना का युक्तियुक्तकरण तथा विस्तार किया जा रहा है। साथ ही दो नई राज्य स्तरीय सेवायें वित्त सेवा एवं राजस्व सेवा गठित की जा रही हैं।

26. नगरीय क्षेत्रों में निवासरत कमजोर एवं निम्न आय वर्गों के लिये राज्य सरकार ने नगर-निकायों, नगर विकास प्राधिकरणों एवं गृह निर्माण मंडल के माध्यम से अटल आश्रय योजना प्रारंभ की है। अब तक 10,000 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

27. चिन्ताजनक रूप से घटता कन्या शिशु लिंग अनुपात बेटी बचाओ आन्दोलन के मूल में है। यह कार्य समाज की सहभागिता से ही पूरा हो सकता है। प्रसन्नता की बात है कि समाज के सभी वर्ग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मेरी सरकार की कुछ यशस्वी योजनाएं जैसे लाड़ली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बेटियों को बोझ न मानने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं। अब ऐसे दंपत्तियों के लिये, जिनकी केवल बेटियां हैं, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारंभ की जा रही है।

28. महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिये मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों के शीघ्रता से निपटारे के लिये 9 जिलों में पृथक अपर जिला सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं। दो वर्षों में 52 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय और 86 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित किये जाएंगे।

महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के लिये महिला हेल्प लाइन 1090 स्थापित होते ही अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों का डाटाबेस बनाया जा रहा है। पुलिस, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं की काउंसिलिंग एवं उनसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

29. युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक विवेकानंद युवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। युवाओं को विकास की धारा से जोड़ने हेतु युवा पंचायत का आयोजन किया गया। युवा अपनी नियति के स्वयं निर्धारक बन सकें, इसलिए उनके आर्थिक स्वालंबन की दिशा में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के रूप में एक ठोस पहल की जा रही है। इस योजना में मेरी सरकार युवाओं को व्यापार, उद्योग, सेवा केन्द्र आदि के लिये 25 लाख की सीमा तक ऋण सुविधा दिलायेगी। रुपये 50 हजार की सीमा तक के उपक्रमों पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी सरकार देगी। इस योजना में सभी ऋणों पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान भी दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा कान्ट्रेक्टर योजना के जरिये इंजीनियरिंग स्नातक एवं डिप्लोमाधारकों के लिये इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।

30. मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो रणनीति अपनाई उसमें शिक्षा से तदर्थवाद खत्म करने, शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न करने, शिक्षा की सुलभता बढ़ाने, योग एवं नैतिक शिक्षा के साथ-साथ हमारे इतिहास के उपेक्षित जननायकों को पाठ्य-वस्तु में शामिल करने, बालिका शिक्षा पर अधिक जोर देने और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के पहलुओं को जोड़ा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 2.65 लाख वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल कराया गया है। प्रत्येक जिले के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रावीण्य सूची के आधार पर देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थानों यथा आई.आई.टी., मेडिकल, चार्टेड एकाऊण्टेंट आदि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 2012 में सुपर-100 योजना जिला इंदौर के शासकीय मल्हाराश्रम स्कूल में आरम्भ की गई है। शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से विगत 10 वर्षों में लगभग 40 हजार नवीन शालाओं की स्थापना की गई है, जहां वर्ष 2003 में प्रदेश में कुल 79 हजार 334 शालाएं थीं वहीं वर्ष 2013 में प्रदेश में 1 लाख 19 हजार 553 शालाएं हैं।

शासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 12वीं परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें लेपटॉप क्रय हेतु रुपये 25 हजार की राशि प्रदाय की जा रही है। अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को भी लाभान्वित करने के लिये इस योजना का विस्तार किया जायेगा।

31. युवा पीढ़ी को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने पर भी मेरी सरकार द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में काम धंधे के हुनर युवा सीख सकें, इसके लिये पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 113 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। आई. टी. आई. की प्रवेश क्षमता बढ़ाई गई है। इसी उद्देश्य से हाल ही में भोपाल में 'स्किल समिट' का आयोजन किया गया। इसमें देश की जानी मानी संस्थाओं ने हिस्सेदारी की। कौशल उन्नयन गतिविधियों में शासन के पच्चीस विभागों की भूमिका होगी। करीब दो हजार युवकों का प्लेसमेंट भी निजी कम्पनियों में हुआ। मेरी सरकार ने अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय और बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के रूप में लीक से हटकर दो विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं। प्रदेश के महाविद्यालयों में रोजगारमूलक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।

32. मेरी सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए औद्योगिक विकास पर भी विशेष बल दिया है जिससे रोजगार के पर्याप्त अवसर निर्मित किये जा रहे हैं। औद्योगिक संवर्धन नीति 2010 में व्यापक संशोधन करते हुए वृहद और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों के विकास हेतु अनेक प्रकार की रियायतें दी गई हैं। औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार निर्माण हेतु इंदौर में 28 से 30 अक्टूबर, 2012 के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों एवं निवेशकों ने भाग लिया। इस समिट में विभिन्न सेक्टर में 3 लाख 77 हजार करोड़ रुपए के निवेश हेतु 1100 से अधिक निवेश प्रस्ताव निष्पादित किये गये जिससे लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

33. निवेश प्रोत्साहन को बहु-आयामी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, वेयरहाऊसिंग एवं लाजिस्टिक, टेक्सटाइल्स, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन नीतियाँ तैयार की गई हैं। प्रदेश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना को पिछड़े जिले की 'सी' श्रेणी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार तथा उन्नयन हेतु रुपये 566 करोड़ की लागत से 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन्दौर स्थित क्रिस्टल आई. टी. पार्क में आई. टी. कम्पनियों द्वारा कार्य करना प्रारंभ किया जा चुका है। ग्वालियर एवं भोपाल में भी आई. टी. पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कैरियर काउंसलिंग के अन्तर्गत लगभग 55 हजार आवेदकों को काँउसलिंग प्रदान की गई एवं 272 जॉब फेयर आयोजित कर लगभग 40 हजार आवेदकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

34. मेरी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का अभूतपूर्व प्रवर्तन और विस्तार करते हुए कमजोर, पिछड़े गरीब और अशक्त लोगों को समग्र सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है जिससे इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय एक हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के जरिए प्रदेश में श्रम-सुधारों के एक नए युग की शुरूआत की है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां 14 लाख से ज्यादा खेतिहर मजदूरों का पंजीयन किया गया है।

इन्हें आम आदमी बीमा योजना से जोड़ा गया है तथा योजना के हितग्राहियों एवं उनके परिजनों को छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश सहायता और बीमा सहायता उपलब्ध करवाई गयी है। इससे वर्ष 2012-13 में 46 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के जरिए 23.40 लाख भवन एवं संनिर्माण मजदूरों का पंजीयन कर आज हम देश में प्रथम स्थान पर हैं।

35. मेरी सरकार ने अधोसंरचना और भौतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय और कल्याण पर समान रूप से ध्यान दिया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन और सुविधा देने के कार्य को अभूतपूर्व गति दी गई है। अभी तक 13.35 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में 240 करोड़ रुपये का हितलाभ दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों एवं वृद्ध दम्पत्तियों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, को प्रतिमाह 20 किलो खाद्यान्न 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूँ तथा तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।

36. नि:शक्तजन के कल्याण के लिये 'स्पर्श अभियान' के रूप में अभिनव पहल की गई है। इसके अंतर्गत तैयार किये गये स्पर्श पोर्टल को नि:शक्तजन के समग्र कल्याण के लिये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम की श्रेणी में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकार को गोल्ड मेडल दिया है।

37. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना देश के इतिहास में अपने किस्म की अकेली योजना है। इसके अंतर्गत मेरी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किसी धार्मिक अथवा जातिगत भेद के बिना जीवनकाल में एकबार धार्मिक स्थल की यात्रा करवाई जा रही है। इस योजना से अभी तक 44 हजार वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल चुका है।

38. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य आयोजना में जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक राशि प्रावधानित करने की व्यवस्था की गयी है। कोई भी पात्र व्यक्ति वनाधिकार से वंचित न रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

अब तक कुल एक लाख 81 हजार से अधिक दावा अधिकार मान्य किये गये हैं। शिष्यवृत्ति की दरों को मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है। इस साल 28 विकासखण्डों में अंग्रेजी माध्यम की आश्रम शालाएँ तथा 5 नये प्री-मेट्रिक छात्रावास खोले गये हैं। विशेष भर्ती अभियान में अब तक 33 हजार 293 पद भरे गये हैं। अभियान की अवधि 30 जून 2013 तक बढ़ा दी गयी है। इन वर्गों के 35 हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। राज्य में जनजातीय बहुलता और सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। पिछड़े वर्ग के कल्याण को गति देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा नवीन जिला कार्यालय स्थापित किये गये हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर 100 सीट वाले पोस्ट मेट्रिक बालक छात्रावास बनाये जा रहे हैं। गत वर्ष ही 12 नये छात्रावास बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु 119 नवीन प्रिमेट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये गए हैं। इसी प्रकार 3 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास एवं 3 नवीन संभागीय आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गए हैं।

पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति 2003-04 की तुलना में 2012-13 में दुगुनी से अधिक हो गई है, जबकि पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 14 गुनी से अधिक हो गई। प्रावीण्य छात्रवृत्ति 7 गुनी बढ़ी है। उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार गारंटी प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, म. प्र. पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।

39. मेरी सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के गुणात्मक विकास, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वचनबद्ध है। 'सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए' की अवधारणा ग्राम को धुरी मानकर समुदाय आधारित कार्य योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन को महत्व देती है। मेरी सरकार के प्रयासों से विगत वर्षों में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी आई है। इस कार्य को और गतिशील करने की आवश्यकता है।

40. राज्य के समस्त नागरिकों को शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क औषधि वितरण के लिये 'सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना' शुरू की है।

इसी माह एक फरवरी से इन संस्थाओं में निःशुल्क चिकित्सीय जाँच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। बीमारियों अथवा प्रकोप आदि के संबंध में जानकारी तीव्रता से प्रसारित करने के उद्देश्य से 'आशा' एवं 'ए. एन. एम.' कार्यकर्ता तथा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संपर्क सेतु योजना के तहत् मोबाइल 'सिम' प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ ग्राम मुख्यालयों से सीधे जुड़ गये हैं। राज्य के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण दूरस्थ क्षेत्रों से स्वास्थ्य सुविधाओं तक रोगियों का परिवहन एक जटिल समस्या थी। मेरी सरकार ने राज्य में संजीवनी-108 के अंतर्गत 602 आपात कालीन परिवहन सेवा प्रारंभ कर राज्य के समस्त जिलों में इस समस्या का समाधान किया है। शीघ्र ही प्रदेश के 34 जिला अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट भी स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में महिलाओं में तीन तरह के कैंसर की जाँच एवं निदान हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों में आगामी दो माहों में विशेष कैंसर उपचार शिविर लगाये जा रहे हैं।

41. स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामोन्मुखी किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से राज्य में 49,340 ग्राम आरोग्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन्हें ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों से जोड़ा गया है।

यह संरचना ग्राम स्तर पर ही स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण में प्रभावी हस्तक्षेप कर सकेंगी। राज्य के समस्त नागरिकों को निःशुल्क औषधियाँ, निःशुल्क चिकित्सीय जांच, निःशुल्क परिवहन सुविधा तथा शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को निःशुल्क पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य प्रदाय सेवाओं के लोकव्यापीकरण का यह एक अभिनव रणनीति सिद्ध होगी। सेवाओं के प्रदाय में गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं प्रतिबद्धता का समावेश करना मेरी सरकार का लक्ष्य है।

42. आयुर्वेद हमारे देश की पारम्परिक धरोहर है तथा इसे चिकित्सा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। राजधानी में हाल ही में विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश-विदेश के 3000 से अधिक आयुर्वेदाचार्यों ने शिरकत की। राज्य में सभी जिला चिकित्सालयों में आयुष केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा इसके साथ ही 148 नये आयुष औषधालय खोले जा रहे हैं।

43. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य के कर्मचारियों के भत्तों की दरें पुनरीक्षित की गई हैं। कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की दर केन्द्र के समान की गई है। प्रदेश के शासकीय अमले के मनोबल को बढ़ाने के लिये उत्कृष्ट कर्मचारियों को नकद राशि से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु 'सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार' की स्थापना की गई है।

44. हज यात्रियों की सुविधा के लिये भोपाल हज हाउस के लिये ग्राम सिंगारचोली में भूमि आवंटित हो गई है। निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जायेगा। इंदौर में भूमि आरक्षित कर ली गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिये छात्रवृत्तियों का लक्ष्य इस बार 17.43 लाख है। इस संबंध में भी प्रदेश अग्रणी है। म. प्र. वक्फ बोर्ड के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। भारत सरकार ने इसे मॉडल के रूप में रखा है और सराहना की है। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार, अल्पसंख्यक बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण योजनाएं भी मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।

45. प्रदेश में व्यवस्थित, नियोजित एवं चरणबद्ध रूप से बुनियादी खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए पिछले वर्षों में प्रदेश के खेल बजट में 25 गुना से ज्यादा वृद्धि करने के साथ ही मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। भोपाल के ओबेदुल्ला खाँ गोल्ड कप हाकी टूर्नामेन्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया है।

ग्राम स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 8403 खेल मैदानों को विकसित किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिये मुख्यमंत्री खिलाड़ी कल्याण कोष बनाया गया है। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि दोगुनी की गई है। वर्ष 2020 के ओलम्पिक में मार्शल आर्ट, शूटिंग एवं वाटर स्पोर्ट विधा के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। 'माँ तुझे प्रणाम' योजना के माध्यम से देश की सीमाओं पर युवाओं को सेना के साथ देश की सीमा पर प्रचलित गतिविधियों से परिचित कराने हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

46. प्रदेश में रोजगार एवं निवेश के लिए पर्यटन की संभावनाओं का भरपूर दोहन करने की रणनीति अपनाई गई है। अधोसंरचना में सुधार तथा बेहतर सुविधाओं के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2006 के मुकाबले वर्ष 2011 तक लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2010 की प्रदेश की पर्यटन नीति संशोधित की जाकर 2012 में पुनः जारी की गई है। इस नीति के तहत प्रदेश में पर्यटन के सभी स्वरूपों के विस्तारण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म, ईको एण्ड एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन सहित सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

47. प्रदेश में विघटनकारी और उग्रवादी तत्वों पर निरन्तर कार्रवाई की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटनाओं के कई आरोपियों को न केवल पकड़ा गया है बल्कि घटनाओं को घटित होने से रोका भी गया है। बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस तथा होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान 11,000 नये पद निर्मित किये गये हैं। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिये नवीन महिला अपराध शाखा का गठन कर प्रथम चरण में 500 नवीन पद सृजित कर पदस्थापनाएँ की जा रही हैं और पुलिस कर्मियों के लिये इस साल 4000 आवास बनाये जा रहे हैं। पुराने आवासों की मरम्मत भी की जा रही है। होमगार्ड सैनिकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिये शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इन्हें देय प्रतिदिन मानवेतन एवं भोजन राशि 190/- रुपये से बढ़ाकर 300/- रुपये कर दी गई है। प्रदेश के दो जिला जेल बैतूल एवं धार में इस वर्ष आई.टी.आई. प्रारंभ कर तीन ट्रेड में बंदियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के 8 केन्द्रीय जेलों को VTP के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है।

48. मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेय प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखकर जन-समस्याओं के समाधान की दिशा में अभिनव सफल प्रयोग किये हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। वर्ष 2013 को 'आई. टी. सशक्तीकरण वर्ष' घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश में लागू की गई लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ का पुरस्कार मिला है। वर्तमान में अधिसूचित 52 सेवाओं के अतिरिक्त लोकहित की अन्य नवीन सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है एवं 10.77 लाख ऑनलाईन आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। अब तक 259 लोक सेवा केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है एवं इनमें से 227 लोक सेवा केन्द्र शुरू हो चुके हैं। मेरी सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये ई-गवर्नेंस, ई-टेंडरिंग, ई-उपार्जन, ई-भुगतान और ई-मेजरमेंट में अभिनव पहल की है। विभिन्न शासकीय विभागों में ऑनलाईन परीक्षा द्वारा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा का विकासखण्ड स्तर तक विस्तार किया गया है। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में स्टेट आई. टी. सेंटर का इसी साल शुभारंभ किया गया है।

49. उदीयमान मध्यप्रदेश की अनेक उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। लोकतंत्र का रथ पक्ष और विपक्ष के दोनों पहियों से गतिमान होता है। मेरा विश्वास है कि प्रदेश का विकास मिला जुला उत्तरदायित्व है जिसे निभाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचारों का आदान प्रदान करने की जरूरत है। बाहरवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत बहुत अच्छी हुई है। इस योजनाकाल में हमें अपने प्रदेश को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सदस्यगणों के ज्ञान, विवेक, अनुभव और विचारों की इसमें महत्वपूर्ण, प्रभावी और रचनात्मक भूमिका रहेगी।

जय हिन्द।

जय मध्यप्रदेश।